आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)
(Eighth Five Year Plan, 1992-97)

आठवीं पंचवर्षीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई दिशाओं में काम करने की दृष्टि से तैयार की गई थी। अतः **रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न करना इस योजना का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था।** आठवीं योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

1. पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन ताकि बीसवीं शताब्दी के अन्त तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
2. लोगों के सहयोग द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकना।
3. सभी को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा 15-35 के आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन।
4. सुरक्षित पेयजल का प्रावधान तथा सभी गांवों में और समूची आबादी के लिए रोग-प्रतिरोधी टीका लगाने समेत प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
5. कृषि के क्षेत्र में संवृद्धि और विविधीकरण ताकि खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ निर्यात के लिए भी अधिशेष (surplus) प्राप्त किया जा सके।
6. ऊर्जा, परिवहन, संचार, परिवहन को मजबूत बनाना।

इन उद्देश्यों के अनुसार काम करते हुए आठवीं योजना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया : (*i*) निवेश कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन एकत्रित करने के लिए घरेलू संसाधनों (domestic resources) पर निर्भरता; (*ii*) विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीकी क्षमता में वृद्धि; तथा (*iii*) आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर जोर ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में हो रही प्रगति के साथ कदम मिलाकर चल सके।

आठवीं योजना में मानव विकास पर खास ध्यान दिया गया। रोजगार सृजन, जनसंख्या नियन्त्रण, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, आधारभूत संरचना का विकास इत्यादि सभी प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों का उद्देश्य इसी मानव विकास को प्राप्त करना था। मानव-पूँजी (human capital) के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की मौलिक जिम्मेदारी सरकार की मानी गई। यह बात हैरानी की लगती है कि उद्देश्यों की उपरलिखित सूची में आर्थिक संवृद्धि को शामिल नहीं किया गया। परन्तु यदि हम योजना के लक्ष्यों की ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि आठवीं योजना में आर्थिक संवृद्धि का लक्ष्य 5.6 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया था जो सम्पूर्ण योजना अवधि में प्राप्त संवृद्धि दर से अधिक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आठवीं योजना में भी आर्थिक संवृद्धि का महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहा।

पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय कुशलता के साथ-साथ योजना के उद्देश्यों के प्रति ईमानदारी जरूरी थी। इसके लिए आयोजन की विकेन्द्रित प्रक्रिया की भी आवश्यकता थी ताकि योजना लागू करते समय लोगों की उसमें भागीदारी की गुंजाइश हो।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1992-2007)
(Ninth Five Year Plan, 1997-2002)

योजना आयोग ने औपचारिक ढंग से दावा किया कि **नौवीं योजना का मूल मन्त्र 'सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक संवृद्धि'**

Scanned with CamScanner

था। योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों की चर्चा तो की गई थी लेकिन इनमें से सामाजिक न्याय से जुड़े उद्देश्यों के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में शुरू से ही शक था :

1. पर्याप्त उत्पादक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
2. कीमतों को स्थिर बनाए रखकर अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को और तेज़ करना।
3. सभी को (विशेष तौर पर निर्धन वर्ग को) खाद्यान्नों व पोषक आहार की उचित मात्रा उपलब्ध कराना।
4. एक निश्चित समयावधि के भीतर सभी के लिए पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, तथा मकान आदि जैसी मूलभूत अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
5. जनसंख्या की वृद्धि दर पर रोक लगाना।
6. आम जनता में सामाजिक चेतना जगा कर तथा उसके सहयोग से आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
7. स्त्रियों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों (जैसे अनुसूचित जातियों व जनजातियों, अन्य पिछड़े हुए वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्गों) को इतनी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करना कि वे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन व विकास के साधन बन सकें।
8. आम जनता की भागीदारी पर निर्भर संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं तथा स्व-सहायता समूहों (self help groups) को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
9. आत्म-निर्भरता (self-reliance) की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को और प्रोत्साहित करना।[5]

1991 में आरंभ की गई उदारीकरण प्रक्रियाओं के अनुरूप तथा आठवीं योजना में विकास युक्ति के निजी क्षेत्र की ओर झुकाव के अनुरूप, नौवीं योजना में कहा गया कि "**हमारी विकास युक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारे व्यापक और फैले हुए निजी क्षेत्र को इतना सक्षम बना सके कि वह उत्पादन में वृद्धि, रोजगार-अवसरों के सृजन तथा समाज के आय स्तर में वृद्धि कर पाने की अपनी पूरी संभावनाओं को प्राप्त कर सके। आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजारों के अनुशासन में कार्यरत शक्तिशाली निजी क्षेत्र दुर्लभ संसाधनों के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा जिससे न्यूनतम लागत पर तेज़ आर्थिक विकास हो सकेगा। इसलिए हमारी नीतियों से ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे यह परिणाम पा सकने में सहायता मिले।**"[6] इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में नौवीं योजना में राज्य की भूमिका में इस प्रकार परिवर्तन करने की सिफारिश की गई थी जिससे वह निजी क्षेत्र के नियंत्रण व नियमन से ध्यान हटाकर सामाजिक विकास में (खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक विकास में) अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके। इस प्रकार, **नौवीं योजना में सरकार की विकास युक्ति का उद्देश्य ऐसी आर्थिक व सामाजिक आधारिक संरचना का निर्माण करना था जिसमें निजी क्षेत्र बिना किसी कठिनाई व रुकावट के अपने कार्य-कलाप को कर सके।** अर्थात्, सरकार को बिजली व ऊर्जा की उचित व्यवस्था व प्रसार करने तथा सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे, संचार व्यवस्था, म्युनिसिपल सेवाओं (municipal services) इत्यादि के विकास व विस्तार पर विशिष्ट ध्यान देना था। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, संगठित ग्रामीण बाजार इत्यादि आएंगे। आधारिक संरचना के विकास व निर्माण के अतिरिक्त, सरकार को मूलभूत सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य सेवाओं तथा पीने की सुविधा इत्यादि) को भी आम जनता को (विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में) उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना था। **औद्योगिक क्षेत्र में विकास युक्ति का प्रयास यह था कि निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबन्धों को कम से कम किया जाए तथा निजी क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में नौकरशाही तंत्र व सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो।** जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, अन्ततः उनके निजीकरण के उद्देश्य से विनिवेश (disinvestment) की नीति जारी रखी गई और विनिवेश से जो संसाधन प्राप्त होने थे उनको सामाजिक क्षेत्रों (विशेष तौर पर स्वास्थ्य व शिक्षा) की योजनाओं पर खर्च करने का वादा किया गया। जहां तक विदेशी क्षेत्र का संबंध है, इसमें युक्ति इस प्रकार की रही कि आयात प्रशुल्क दरों को कम किया गया एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, निर्यातों के प्रसार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तथा निर्यात प्रोत्साहन में सहायता देने के लिए विदेशी विनिमय दर नीति का प्रयोग किया गया, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाए गए।

Scanned with CamScanner